International Journal of Literacy and Education

E-ISSN: 2789-1615
P-ISSN: 2789-1607
Impact Factor: 5.69
IJLE 2023; 3(1): 169-172
www.educationjournal.info
Received: 26-02-2023
Accepted: 06-04-2023

संजय कुमार वर्मा
शोध छात्र शिक्षा, लाइफ लॉंग लर्निंग विभाग, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. स्वर्णलता त्रिपाठी
विभागाध्यक्ष शिक्षा, श्रीयुत्त स्नातकोत्तर कालेज, गंगेव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
संजय कुमार वर्मा
शोध छात्र शिक्षा, लाइफ लॉंग लर्निंग विभाग, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अपेक्षाकृत 2020 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का अध्ययन

संजय कुमार वर्मा एवं डॉ. स्वर्णलता त्रिपाठी

सारांश
इस शोध पत्र के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अपेक्षाकृत 2020 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का अध्ययन किया गया है। शोध क्षेत्र के प्रत्येक विकासखण्ड से न्यादर्श के रूप में चयनित रीवा जिले के सभी विकासखण्डों से 5–5 विद्यालय कुल 45 प्राथमिक विद्यालयों, प्रत्येक विद्यालयों से 10–10 छात्र–छात्राएँ कुल 900 का चयन दैव निदर्शन पद्धति से अधिगम स्तर ज्ञात करने के लिए किया गया है। शोध क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सार्थक अन्तर है। शोध क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के अधिगम स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

कूट शब्दः रीवा जिला, प्राथमिक स्तर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020, प्रभाव, विद्यार्थी, अधिगम स्तर

1. प्रस्तावना
आज विश्व के सभी देशों में प्रारंभिक शिक्षा को जन जन को सुलभ बनाने के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे है। यही कारण है कि प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर जितने बालक – बालिकाएँ अध्ययन हेतु विद्यालय में सुलभ होते है, उतना अन्य किसी स्तर पर नहीं। इसलिए प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों की संख्या माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक हैं। आज भी बहुत से अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के अधिकांश बालक–बालिकाएँ मात्र प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् जीवन के मुख्य धारा से जुड जाते है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु जिनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया गया–

- भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु सम्पूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया।
- शिक्षा के उत्तम क्रियान्वयन हेतु शिक्षा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिले के अनुसार विभाजित किया गया।
- इसमें छात्रों के व्यावहारिक पक्ष एवं शारिरिक पक्ष पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा में इनको मुख्य स्थान दिया गया। जिससे शिक्षा के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सकें।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (Rashtriya Shiksha Niti 1986) में देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया एवं बुनियादी शिक्षा Basic Education के स्वरूप को स्वीकार किया गया।
- प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए ब्लैकबोर्ड योजना का निर्माण किया गया एवं 90 प्रतिशत छात्रों को इसके द्वारा लाभ पहुचाने की योजना का निर्माण किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ऐसी नीति थी जिसको सफलतापूर्वक लागू करने का सम्पूर्ण प्रयास किया गया परंतु यह कहना गलत होगा कि यह अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रहीं यह हम इसीलिये कह रहे हैं कि अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली सभी को रोजगार प्राप्त करवाने हेतु असमर्थ साबित हुई हैं।
शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है। जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएं निहित होती हैं। शिक्षा नीति की दृष्टि से विडंबना यह रही कि 1968 में पहली और 1986 में दूसरी शिक्षा नीति के बाद सरकारों के द्वारा शिक्षा का क्षेत्र उपेक्षित छोड़ दिया गया। यद्यपि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधुनिकीकरण पर केंद्रित कही जाती है, जिसमें देश में शिक्षा के विकास के लिए व्यापक ढांचा, शिक्षा के आधुनिकीकरण और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर देने की बात कही गई थी। किंतु 1990 के दौर में भूमंडलीकरण की

प्रक्रिया ने व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकता में आमूलचूल परिवर्तन किए, जिन्हें पूरा करने में शिक्षा नीति 1986 सक्षम नहीं रही। निरक्षरता की दर निरंतर बढ़ती रही, ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित ही रहे। विद्यालय तथा महाविद्यालयों की ढांचागत एवं अध्ययन–अध्यापन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियां अभी तक भी देखी जा सकती हैं। वर्ष 2014 में बहुमत में आई मोदी सरकार के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ी चुनौती एवं आवश्यकता के रूप में सामने थी। जिसे देखते हुए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया। तत्पश्चात केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने एक व्यापक लोकतांत्रिक नीति अपनाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित देश के कोने–कोने से सभी वर्गों के लोगों की राय ली। यह प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की भावना पर आधारित दिखाई देता है।

षिक्षण संबंधी प्रावधान :

- नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।
- पाँच वर्ष की फाउंडेषनल स्टेज (Foundational Stage) . 3 साल का प्री–प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2.
- तीन वर्ष की प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage)
- तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण – ग्रेड 6, 7, 8 और
- 4 वर्ष का उच्च (माध्यमिक) चरण – ग्रेड 9, 10, 11, 12

NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राश्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्श 2025 तक कक्षा – 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौषल सुनिष्चित किया जाएगा।

2. अध्ययन की आवश्यकता :

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अपेक्षाकृत 2020 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का आकंलन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा स्तर पर योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से विकसित करने में समर्थ हो सकता है। आज भारत ज्ञान–विज्ञान, सूचना–प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संकल्पित किया जा चुका है। ऐसे में नई शिक्षा नीति प्रभावी होगी और यह नए भारत की नींव सिद्ध होगी। यह षोध कार्य पूरे प्रदेष के लिए नवीन है इसलिए इसके प्राप्त सुझाव शिक्षा के विकास हेतु उपयोगी होंगे।

3. उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया है:–

1. शोध क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. शोध क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. शोध की परिकल्पनाएँ:

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् है:–

1. शोध क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।
2. शोध क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

5. शोध समस्या का सीमांकन :

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र जिला रीवा है। इसके अन्तर्गत 9 विकासखण्ड – रीवा, रायपुर कर्चुलियान, सिरमौर, जवा, हनुमना, गंगेव, त्यौथर, नईगढ़ी एवं मऊगंज हैं। अतः जिला अन्तर्गत प्राथमिक स्तर के विद्यालय इस अध्ययन सम्मिलित किए गए है।

6. शोध विधियाँ :

शोध कार्य को संपूर्णता प्रदान करने हेतु कई प्रकार की शोध विधियों का उपयोग किया जाता है। शोध विधियों के मुख्य प्रकार ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक है। शोध कार्य के अनुरूप प्रत्येक शोध विधि की अपनी विशेषताएँ एवं उपयोगिता है। शैक्षिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रस्तुत शोध कार्य मुख्य रूप से सर्वेक्षणात्मक (वर्णनात्मक) होगा। शोध अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

6.1 सर्वेक्षण विधि – प्राथमिक स्त्रोतों से प्रदत्तों के संकलन एवं पूर्व संचालित प्रदत्तो के सत्यापन हेतु शोध क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया है।

6.2 सांख्यिकी विधि – प्रयुक्त शोध उपकरणों से प्राप्त प्रदत्तों के सारणीयन के उपरान्त आवश्यकतानुसार माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, दो चरों में सार्थक अन्तर के आंकलन हेतु मध्यमान विचलन, टी–परीक्षण जैसी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

शोध उपकरण – सूचना या आंकड़े प्राप्त करने हेतु स्वनिर्मित अधिगम परीक्षण पत्रक का प्रयोग किया गया है।

7. न्यादर्श चयन :

अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी समस्त सूचनाओं को दिया जाता है। शोध कार्य को सार्थक करने के लिए न्यादर्श का चयन किया जाता है। न्यादर्श के रूप में चयनित रीवा जिले के सभी विकासखण्डों से 5–5 प्राथमिक विद्यालय कुल 45 विद्यालयों, प्रत्येक विद्यालय से 10–10 छात्र–छात्राएँ कुल 900 का चयन दैव निदर्शन पद्धति से अधिगम स्तर ज्ञात करने हेतु किया किया गया है। इस प्रकार यह अध्ययन दोनों दृष्टियों से सैद्धान्तिक एवं अनुभवाश्रित परिपूर्ण होगा।

8. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का विवरण :

किसी भी शोध कार्य को सोद्देश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के समरूप पूर्व में किए गये अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने शोध क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अपेक्षाकृत 2020 के

क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का अध्ययन पर पड़ने वाले प्रभाव पर किये गये कुछ प्रमुख तथा सहज रूप से उपलब्ध पूर्व शोध अध्ययनों के विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – अग्रवाल, आर. एवं अरीना, विपिन (1989)[1], कुशवाहा, उमाशंकर एवं श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार (2021)[2], कपिल, एच.के. (1996)[3], खुल्लर, के.के. (1988)[4], गहरवार मिथलेस सिंह (2005)[5], चतुर्वेदी, आर.सी. एवं मिश्रा, शिवानी (2007)[6], सिंह, बिरेन्द्र एवं देवी कुकन (2022)[7], पाठक, सच्चिदानंद (2021)[8], साईद, असलम एवं शुक्ला, प्रतिमा (2022)[9]।

9. शोध क्षेत्र का परिचय :

जिला रीवा मध्य प्रदेश के उत्तरी–पूर्वी कोने में स्थित है। रीवा का नामकरण नर्मदा नदी के दूसरे नाम 'रेवा' पर आधारित है। रीवा नगर का नाम पहले शायद 'रेवा' रखा गया था। उसी का बिगड़ा रूप अब रीवा बन गया है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा पूर्व–उत्तर में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में अपने राज्य का सीधी जिला और दक्षिण–पश्चिम तथा पश्चिम में सतना जिला है। इसका आकार लगभग त्रिभुज के समान है। इसका विस्तार 24.18^0 उत्तरी अक्षांश से 25^0 उत्तरी अक्षांश तथा 81.2^0 पूर्वी देक्षांश से 82.18^0 पूर्वी देक्षांश के मध्य है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287 वर्ग किलोमीटर है।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

परिकल्पना क्र. 1 : शोध क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में कोई सार्थक अन्तर नही है।

सारणी क्रमांक 1: शोध क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

समूह		ग्रामीण	शहरी
समूह की संख्या (N)		360	540
मध्यमान (M)		60.44	64.94
मानक विचलन (SD)		17.12	15.65
क्रान्तिक निष्पत्ति ('t')		4.00	
निष्कर्ष	0.05 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	
	0.01 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	

$df = (N_1-1) + (N_2-1)$
$df = (360-1) + (540-1) = 359+539 = 898$

उपरोक्त सारणी क्रमांक 1 मे न्यादर्श में चयनित शोध क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर से सम्बधित प्रदत्त संकलित किये गये हैं। संकलित प्रदत्त प्राथमिक स्त्रोत पर आधारित है। सारणी में संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 60.44 है तथा मानक विचलन 17.12 है और शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 64.94 है तथा मानक विचलन 15.65 है।

798 df पर सार्थकता के लिए श्जश का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.62 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर 1.98 है, जबकि अध्ययन से प्राप्त 't' का मान 4.00 है, जो कि दोनो विश्वास स्तरों के मानों से अधिक है। अतः शोध क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सार्थक अन्तर है। अतः परिकल्पना क्र. 1 निरसित होती है।

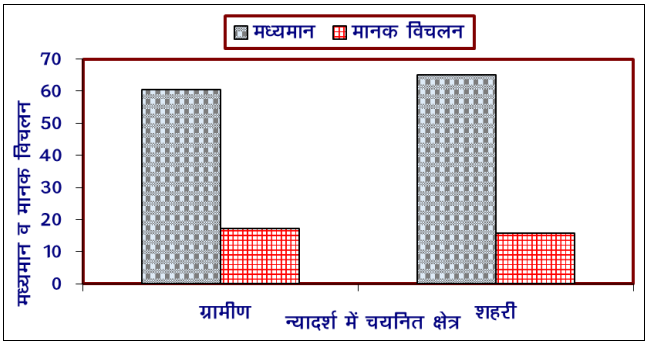

आरेख क्र. 1: शोध क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

परिकल्पना क्र. 2: "शोध क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के अधिगम स्तर में कोई सार्थक अन्तर नही है।"

सारणी क्रमांक 2: शोध क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

समूह		छात्र	छात्राएँ
समूह की संख्या (N)		450	450
मध्यमान (M)		62.29	61.69
मानक विचलन (SD)		15.91	16.44
क्रान्तिक निष्पत्ति ('t')		0.56	
निष्कर्ष	0.05 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर नहीं है	
	0.01 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर नहीं है	

$df = (N_1-1) + (N_2-1)$
$df = (400-1) + (400-1) = 399+399 = 798$

उपरोक्त सारणी क्रमांक 2 मे न्यादर्श में चयनित शोध क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के अधिगम स्तर से सम्बधित प्रदत्त संकलित किये गये हैं। संकलित प्रदत्त प्राथमिक स्त्रोत पर आधारित है। सारणी में संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 62.29 है तथा मानक विचलन 15.91 है और छात्राओं के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 61.69 है तथा मानक विचलन 16.44 है।

798 df पर सार्थकता के लिए 't' का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.62 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर 1.98 है, जबकि अध्ययन से प्राप्त 't' का मान 0.56 है, जो कि दोनो विश्वास स्तरों के मानों से कम है। अतः शोध क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के अधिगम स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अतः परिकल्पना क्र. 2 सत्यापित होती है।

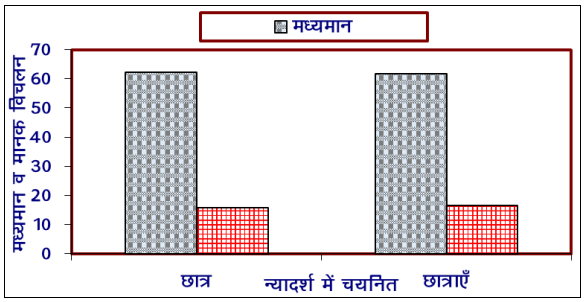

आरेख क्र. 2: शोध क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

निष्कर्ष :

शोध क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 60.44 है तथा मानक विचलन 17.12 है और शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 64.94 है तथा मानक विचलन 15.65 है।

शोध क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 62.29 है तथा मानक विचलन 15.91 है और छात्राओं के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 61.69 है तथा मानक विचलन 16.44 है।

संदर्भः

1. अग्रवाल, आर. एवं अरीना, विपिन (1989): मनोविज्ञान एवं शिक्षा में मापन व मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.
2. कुशवाहा, उमाशंकर एवं श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार (2021): सतना जिले में किशोरावस्था के छात्र व छात्राओं में मानवीय मूल्यों का उनकी शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, International Journal of Applied Research. 2021;7(1):400-403.
3. कपिल, एच.के. (1996): सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.
4. खुल्लर, के.के. (1988): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई दिल्ली विज्ञापन एवं दृष्य प्रसार निर्देशालय.
5. गहरवार मिथलेस सिंह (2005): रीवा जिले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के शैक्षिक नवाचारो का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभावशीलता का समीक्षात्मक अध्ययनः अप्रकाशित शोध ग्रंथ शिक्षा, अ.प्र.सिं.वि.वि.रीवा.
6. चतुर्वेदी, आर.सी. एवं मिश्रा, शिवानी (2007): वर्तमान भारतीय शिक्षा, समाज और भ्रष्टाचार, Research Journal of Social and Life Sciences. 2007;2(1):195–204.
7. सिंह, बिरेन्द्र एवं देवी कुकन (2022): उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतदृष्टि, International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR). 2022;9(1):17-20.
8. पाठक, सच्चिदानंद (2021) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानः एक अध्ययन, Multidisciplinary Academic Research. 2021;18(6):216-220.
9. साईद, असलम एवं शुक्ला, प्रतिमा (2022): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों और अवसरों पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT). 2022;2(1):127-131.